जनसत्ता

कानून के हाथ

भारतीय राजनीति में रसूखदार नेताओं का रुतबा किस कदर हावी रहता है, यह अनेक मौकों पर अलग-अलग तरह के मामलों में साबित होता रहा है। बलात्कार के आरोपों के बाद स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी से पहले समूचे जांच दल, प्रशासन और पुलिस तंत्र का ऊहापोह से गुजरना भी यही दर्शाता है कि ऊंचे पद-कद वाली शख्सियतों के मामले में कैसे नरम और भिन्न रुख अख्तियार किया जाता है। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने वीडियो सार्वजनिक करते हुए स्वामी चिन्मयानंद पर उसके समेत कई अन्य लड़कियों का शोषण करने और धमकाने का आरोप लगाया था। कई दिनों तक लगातार शिकायत के बावजूद जब पुलिस ने टालमटोल का रवैया बनाए रखा तब लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन और सरकार के दबाव में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिस तरह के मामले में सरकार को तुरंत सक्रिय और संवेदनशील होकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, शोषण और धमकी से संबंधित कई वीडियो वायरल होने के बावजूद उसने चुप्पी लगाए रखी। जबकि कुछ वकीलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को जांच के लिए एसआइटी बनाने का भी निर्देश दिया।

इस प्रकरण में चर्चा में आए वीडियो सहित जिस तरह के आरोप थे, उसमें कार्रवाई को लेकर पुलिस का रवैया टालमटोल वाला और हैरानी भरा रहा। हालत यह थी कि कुछ दिन पहले जब लड़की ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि क्या पुलिस तब सक्रिय होगी जब वह आग लगा कर आत्महत्या कर लेगी, तब जाकर अब आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। पीड़ित लड़की के आरोप कितनी मजबूत बुनियाद पर खड़े थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद स्वामी चिन्मयानंद ने अपने ऊपर लगे लगभग सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। सवाल है कि करीब महीने भर पहले आए आरोपों के बावजूद पुलिस का तंत्र आखिर किन वजहों से कार्रवाई से हिचक रहा था? लगभग आठ साल पहले भी स्वामी चिन्मयानंद के ही आश्रम में एक महिला ने यौन शोषण और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार ने उस मुकदमे को वापस ले लिया था। फिलहाल उस मामले में हाईकोर्ट का स्थगनादेश मिला हुआ है।

आमतौर पर बलात्कार या फिर यौन शोषण के मामलों में आरोप सामने आने और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करती है और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। लेकिन ऐसे आरोप आम हैं कि ऊंचे कद-पद वाले नेताओं के खिलाफ जब कोई शिकायत करता है तब सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक उसे संरक्षण देती है या उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जहां तक स्वामी चिन्मयानंद से जुड़े मामले का सवाल है तो पीड़ित लड़की ने जिस तरह की धमकी मिलने की बात कही है, उसे नजरअंदाज करना उसके जीवन को जोखिम में डालने से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में एक भाजपा नेता पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके परिवार को किस तरह की त्रासदी से गुजरना पड़ा, यह सब जानते हैं। यहां तक कि कुछ समय पहले एक ट्रक से हादसे के बहाने उसकी हत्या तक करने की कोशिश की गई। ऐसे में भारतीय राजनीति में स्वामी चिन्मयानंद के पद-कद और रसूख को देखते हुए सरकार को इस मामले में पहले पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ समुचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाना सरकार की निष्पक्षता और न्यायप्रियता की कसौटी होगी।

तालिबान की हिंसा

अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, तालिबान की हिंसा का ग्राफ भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब आत्मघाती हमलों से अफगानिस्तान के शहर दहल नहीं रहे हों। अस्पताल, सरकारी इमारतें, पुलिस और सुरक्षा बलों के ठिकाने, यहां तक कि अमेरिकी दूतावास तक पर तालिबान के हमले यह संदेश दे रहे हैं कि इस देश की सत्ता पर फिर से कब्जे के लिए वह पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। दूसरी ओर तालिबान को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी सेना के हमले भी जारी हैं। दो दिन पहले एक अमेरिकी ड्रोन के हमले में बीस से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। अमेरिका और तालिबान को इस बात से तनिक चिंता नहीं है कि इन दोनों के झगड़े में निर्दोष अफगान जनता बुरी तरह पिस रही है। हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता टूटने के बाद तो हालात बेकाबू हो गए हैं। तालिबान ने और ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया है। ऐसे में सवाल है कि इस हिंसा के बीच अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव कैसे होंगे। अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि सभी अफगान नागरिकों को 'भय और हिंसा मुक्त' जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यह कैसे सुनिश्चित हो, इसके उपाय इस वैश्विक निकाय के पास भी नहीं हैं।

अफगानिस्तान में इस वक्त हिंसा का जो दौर चल रहा है उसने पूरे देश को फिर उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जो दो दशक पहले बनी हुई थी। इन हालात के लिए क्या तालिबान दोषी है या फिर अमेरिका या अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार, यह सवाल फिलहाल दब-सा गया है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता तोड़ने जैसा कठोर कदम नहीं उठाते तो शायद आज हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन एक अमेरिकी सैनिक की मौत के मामले पर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को हिंसा की आग में झोंक डाला। हालांकि पिछले साल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को एक राजनीतिक पार्टी की मान्यता देते हुए जेल में बंद उसके लड़ाकों को रिहा करने का बड़ा फैसला लिया था। तालिबान के साथ शांति वार्ता की दिशा में यह बड़ा कदम था। इस बीच कतर में शांति वार्ता के दौर तो चलते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। बाद में मास्को में हुई शांति वार्ता में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हुए, लेकिन तब इसमें अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया। तालिबान की शर्त थी कि चुनाव रद्द होने पर ही वह अमेरिका के साथ समझौता करेगा। इस तरह वार्ता राजनीति और अहम की लड़ाई में उलझती रही। तालिबान का अड़ियल रवैया भी इसका एक बड़ा कारण रहा, जिसकी कीमत आज अफगानिस्तान युद्ध के मैदान के रूप में चुका रहा है।

इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होनी चाहिए। यह काम अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान और अमेरिका को ही करना है। इसके लिए जरूरी है कि तीनों अपना हठ छोड़ें और खासतौर से अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हितों को छोड़े। शांति वार्ता रद्द होने से अफगानिस्तान की सरकार खुश है। दूसरी ओर तालिबान अब अमेरिका को सबक सिखाने पर तुला है। इसीलिए उसने शांति वार्ता टूटने के बाद और ज्यादा अमेरिकियों पर हमले की धमकी दी है। जाहिर है, आने वाले दिन अफगानिस्तान के लिए और संकट भरे होंगे।

कल्पमेधा

सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है।

-जयशंकर प्रसाद

असफलताएं सिखाती हैं

जयसिंह रावत

रोहिणी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक शृंखला थी जिसकी सफलता की शुरुआत रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड (आरटीपी) की विफलता की बुनियाद पर हुई थी। इसके बाद भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए रास्ता मिल गया था।

चंद्रयान-2 मिशन को पूरी तरह विफल कहना उचित नहीं होगा। यह अंतरिक्ष मिशन काफी हद तक कामयाब रहा है। इसलिए इस मुकाम पर जश्न मनाने का मौका नहीं मिला तो इसे लेकर निराश होने का भी कोई औचित्य नहीं है। साथ ही, वैज्ञानिकों को यह समझाने या ढाढ़स बंधाने की भी आवश्यकता नहीं है कि विफलताओं से ही सफलता का मार्ग मिलता है। वैज्ञानिक सात सितंबर को उसी वक्त से नई राह तलाशने में जुट गए थे जब विक्रम लैंडर चंद्रमा से मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी से बहक गया था। चांद की सतह पर तिरछे पड़े विक्रम लैंडर को खोज निकालना और उसे पुनः सक्रिय करने के निरंतर प्रयास वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प के द्योतक हैं।

विज्ञान प्रयोगों के आधार पर आगे बढ़ता है। प्रयोग जब विफल होते हैं तो विफलता के कारणों का पता लगाने से ही सफलता का रास्ता बनता है और यह सिलसिला आज से नहीं, मानव विकास के इतिहास के साथ समांतर रूप से चल रहा है। अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल राकेटों का इतिहास भी भिन्न नहीं है। माना जाता है कि किसी निर्जीव वस्तु को आसमान में दागने का प्रयोग ईसा से चार सौ वर्ष पूर्व इटली के टारेंटम निवासी आर्चिटस ने लकड़ी के कबूतर को उड़ा कर किया था। फिर चीन में खोखले बांस से बनाए डंडे में बारूद भर कर उसे दुश्मन पर दागने और मंगोलों द्वारा उसे अपने शस्त्रागार का अंग बनाने के भी संदर्भ मिलते हैं। बहुत दूर के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपने वैज्ञानिकों द्वारा तैयार पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ से और उसकी ही मदद से प्रक्षेपित किया था। इसके बाद ही भारत के राजनीतिक नेतृत्व और वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते अपने ही प्रक्षेपण स्थल से उपग्रह प्रक्षेपित करने का संकल्प लिया था। लेकिन 10 अगस्त 1979 को जब इस संकल्प को पूरा करने की बारी आई तो उपग्रह आसमान में जाने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा था। इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना था, लेकिन ईंधन रिसाव के कारण मिशन विफल हो गया था। तब इस मिशन के निदेशक डा. एपीजे अब्दुल कलाम थे और इसरो अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन थे। बताते हैं तब प्रो. सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर कहा था कि इस मिशन में हम विफल हो गए हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और अगली बार हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे।

इस विफलता के बावजूद डा. कलाम के नेतृत्व में ही मिशन जारी रहा और अंततः 18 जुलाई 1980 को भारत का पहला उपग्रह 'रोहिणी' भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएलवी-3) से प्रक्षेपित कर पृथ्वी की कक्षा में सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया गया था। तब इस ऐतिहासिक सफलता के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सतीश धवन ने स्वयं आगे आने के बजाय डा. कलाम को आगे रखा था। मतलब यह कि विफलता का अपयश लेने वाले इसरो अध्यक्ष ने सफलता का श्रेय भी लेने के बजाय वह स्वर्णिम अवसर डा. कलाम को देकर एक आदर्श नेतृत्व का उदाहरण वैज्ञानिक बिरादरी के समक्ष पेश कर भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी।

रोहिणी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक शृंखला थी जिसकी सफलता की शुरुआत रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड (आरटीपी) की विफलता की बुनियाद पर हुई थी। इसके बाद भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए रास्ता मिल गया था। इसरो द्वारा विकसित किए गए पांच प्रक्षेपण यान एसएलवी-3, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएलवी मार्क-3, जिसका दूसरा नाम एएलवीएम-3 है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपने मिशन पूरे कर चुके हैं। इसरो के अधिकांश उपग्रह स्वदेशी पीएसएलवी और जीएसएलवी राकेटों से ही प्रक्षेपित किए गए। इनमें चंद्रयान प्रथम और मंगल यान भी शामिल हैं। अक्तूबर 1994 से लेकर 2015 तक पीएसएलवी (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) ने एक के बाद एक अट्ठाईस सफलताएं हासिल कीं। इसरो ने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 अक्तूबर, 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी से ही चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया था जो 30 अगस्त, 2009 तक सक्रिय रहा। यह चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इंपैक्ट प्रोब (एमआइपी) 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा गाढ़ने वाला चौथा देश बना।

यही नहीं, पीएसएलवी ने अनेक विदेशी उपग्रहों

को भी प्रक्षेपित किया। इसरो ने पांच जनवरी, 2014 को जीएसएलवी के जरिए श्री हरिकोटा से जीसैट-14 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। उसी साल 18 दिसंबर को यहां एलवीएम-3 एक्स के द्वारा दो बड़े ठोस राकेट बूस्टर और राकेट द्रव्य का परीक्षण किया गया। इसके बाद 15 जनवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी-सी 37 के द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर अंतरिक्ष में भारत की सफलताओं का नया इतिहास रचा था। जून 2016 में इसरो ने एक ही राकेट पीएसएलवी द्वारा बीस उपग्रह प्रक्षेपित किए थे।

चार जुलाई 1957 को दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने वाले सोवियत संघ और फिर 21 जुलाई 1969 को चांद पर अपोलो-11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग को उतारने वाले अमेरिका को भी अंतरिक्ष में सफलताओं के झंडे गाढ़ने से पहले कई बार विफलताओं का सामना करना पड़ा था। सन 1963 में चार जनवरी को स्पुतनिक-25 का सफल प्रक्षेपण तो हुआ था, मगर उसके बाद खराबी के चलते उसका राकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल पाया था। इसके बाद सोवियत संघ के लूना ई-6 (3 जनवरी 1963 को प्रक्षेपित), लूना-4 (2 अप्रैल 1963 को प्रक्षेपित), लूना-ई-6 (21 मार्च 1964 को प्रक्षेपित), कास्मोस-60 (12 मार्च 1965 को प्रक्षेपित), लूना ई-60 (10 अप्रैल 1965 को प्रक्षेपित), लून-5 (9 मई 1965 को प्रक्षेपित), लूना-6 (8 जून 1965 को प्रक्षेपित), लूना-7 (4 अक्टूबर 1965 को प्रक्षेपित), लूना-8 (3 दिसंबर 1965 को प्रक्षेपित), और लूना -18 (2 दिसंबर 1971 को प्रक्षेपित) मिशन विफल रहे थे। लूना-8 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन वह भी आसानी से उतरने के बजाय चांद की सतह पर जा टकराया था। सोवियत संघ ने पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन को 1961 में अंतरिक्ष में भेजा था। भारत का चंद्रयान-2 मिशन में भी 'विक्रम' की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, जो हो नहीं पाई।

इसी तरह अमेरिका ने 20 सितंबर 1966 को सर्वेयर-2 प्रक्षेपित किया था जो चांद की सतह से एक सौ तीस किलोमीटर दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 14 जुलाई 1967 को प्रक्षेपित सर्वेयर-4 भी चांद पर लैंडिंग से ढाई मिनट पहले रेस्ट्रोराकेट में विस्फोट से उसका भी संपर्क धरती के नियंत्रण कक्ष से टूट गया। इस साल (22 फरवरी 2019) चंद्रमा पर उतरने का इजराइल का बेरेशीट मिशन भी विफल रहा।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नया नहीं है और हमारी सफलताएं और विफलताएं भी कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। विज्ञान न केवल आसमान में नई संभावनाएं तलाशने के साथ ही अंतरिक्ष की अबूझ पहेलियों को बूझने का प्रयास कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष और विज्ञान की खोजों माध्यम से धरती पर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनवरत प्रयास हो रहे हैं। इस महान बिरादरी के महान कार्यों का श्रेय छीन कर अपने सिर पर सजाने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। देश में वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

मूंगफली का छिलका

अनिता वर्मा

मूंगफली का छिलका यों तो किसी की दृष्टि में नहीं आता। निरर्थक-सा पड़ा रहता है सिनेमाघरों, ट्रेन के डिब्बों, सड़क पर, खोमचे वालों के बगल में बेकार-सा! जब नजर पड़ जाए किसी सफाई वाले की तो इकट्ठा कर लगा दिए जाते हैं मूंगफली के छिलकों के ढेर। मैंने भी मूंगफली के दानों का रसास्वादन कर समय व्यतीत करने के बाद फेंक दिया छिलकों को लापरवाही के साथ। अब छिलके से किसी को कोई सरोकार नहीं। अब तो हवा का एक झोंका भी उसे डिगा सकता है, उड़ा सकता है। एकत्र छिलकों के ढेर को तेज हवा की रफ्तार तितर-बितर कर देती है एक क्षण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। कोई भी नहीं पूछता उसके हाल। बेकार, निरर्थक और सारहीन जो हो गया है वह हमारी दृष्टि में। कहा भी गया है- 'सार-सार को गही रहे थोथा देई उड़ाय'। तो हमने इस दर्शन को आत्मसात करते हुए 'सारतत्त्व' (दाना) को ग्रहण करते हुए 'असार' (छिलका) को उड़ा दिया, फेंक दिया।

यही आज का दर्शन और चिंतन है। भौतिकतावादी चिंतन का यथार्थ, जहां उपयोग में आने के बाद कोई भी प्रयोग की गई वस्तु फेंक दी जाती है कबाड़ में। 'यूज ऐंड थ्रो' की संस्कृति फलीभूत और पल्लवित हो रही है। फिर छिलके का कोई महत्त्व और अस्तित्व भी तो नहीं होता! तब कौन उसकी परवाह करे, कौन उसके विषय में चिंतन करे! कोने में पड़ा मूंगफली का छिलका यों ही पड़ा रहता है चुपचाप, चुप्पी साधे, बिना किसी भाव के शांत! वह कर भी क्या सकता है, अपनी बेचारगी पर आंसू बहाने के सिवा! इस प्रतिस्पर्धा के युग की अंधी दौड़ में कौन उसे पूछे!

सब भाग रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। मनभावन, चित्ताकर्षक प्रलोभन उस भीड़ का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। कोई किसी से हारना भी नहीं चाहता। घर-परिवार और समाज में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होने का दंभ पाले मदमस्त चाल से थोथे अहं का आवरण ओढ़े भीड़ चली जा रही है। काहे की चिंता कैसी फिक्र..! कौन अपना कौन पराया..! 'हमें क्या करना' जैसे सूत्रवाक्य उनके जीवन का आधार बन गए हैं। ऐसे समय में निरर्थक और अनुपयोगी हो गए मूंगफली के छिलके की क्या बिसात!

दुनिया मेरे आगे

सरसता में ही जीवन की रागात्मकता अंतर्निहित होती है। जीवन सरस और उमंग से भरपूर हो, तभी जीवन की सार्थकता है, वरना नीरस और सारहीन होकर जीना भी कोई जीना है! सरस से नीरस बनने की पीड़ा का कड़वा यथार्थ कौन बयान करे! मैंने जब समसामयिक संदर्भों पर खुद को केंद्रित करते हुए मूंगफली के छिलके की पीड़ा को अनुभूत करने का असंभव प्रयास किया, तब आज के मानव जीवन की सच्चाई मेरे समक्ष आ खड़ी हुई। कुछ कह या समझ पाते, तभी मुझे लगा कि वह छिलका एक प्रेरक या उपदेशक के रूप में जीवंत हो गया है और मुझसे कह रहा है कि 'मेरा और मनुष्य जीवन का सत्य एक-सा ही है। जब तक आप 'सारयुक्त' (दानासहित)होते हैं, तब तक आपकी उपयोगिता बनी रहती है, आप शिरोधार्य बने रहते हैं। 'सारविहीन' (दानारहित) होने पर आप नकार दिए जाते हैं, घर-परिवार और समाज से मूंगफली के छिलके की तरह।

युगों से मानव जीवन इसी गति से चलता जा रहा है, जहां उसकी सोच और चिंतन में युग के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। परिवेश मानव को तेजी से प्रभावित करता है। जब तक किसी की सार्थकता बनी रहती है, वह शिरोधार्य रहता है। फिर 'तुम कौन, हम कौन'। इस संसार में संवेदनाएं सुप्त हो रही हैं। किसी को भी वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर उसे उठा कर फेंक देना। यह कहां का न्याय है? मूंगफली का छिलका जब तक सरस था, तब तक अलग-अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। खाद्य पदार्थ, घरेलू खाद्य व्यंजनों, फलाहार, सर्दियों के मेवे के तरह-तरह के नमकीन- सबमें शामिल किया जाता रहा। और तो और, उसके दानों का तेल निकाल कर बचे अवशेष को भी नहीं छोड़ा जाता। वह भी पशुओं के चारे खल-चूरी के काम आ जाता है। पर समस्या तो छिलके की है। वह किस काम का! उसे तो पशु भी नहीं खाते तो उसे कौन सहेज कर रखे!

यही जीवन का कड़वा यथार्थ है, जिसे समझना और स्वीकार करना इतना आसान भी नहीं होता। आखिर मनुष्य इतनी आसानी से कैसे स्वीकार ले कि आज वह अनुपयोगी हो गया है। वह कोई वस्तु भी तो नहीं, जिसके भीतर कोई स्पंदन न हो, चिंतन न हो। यही चिंतन चिंता में बदल कर निराशा और मनुष्य को अवसाद ग्रस्त बना देता है। यही प्रश्न विचारणीय है। विचारों का प्रवाह कभी रुकता नहीं है और विविध विचारों की यही शृंखला अनवरत चलती रहती है। हर मनुष्य के अंतर्मन में यही कारण है मानव मन के दुख का। उसके भीतर का यह दर्द रह-रह कर उसे टीस देता है। जीवन का यह प्रवाह अबाध गति से आगे बढ़ता जाता है, पीछे छूटता जाता है अतीत। और अतीत को भूल कर आगे बढ़ना ही तो जीवन जीने की कला है।

दावे और हकीकत

श्रम राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर भारत के युवाओं में कौशल की कमी बता कर भले ही एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी हो लेकिन आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयान कर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब युवाओं को नौकरी न दे पाने की तोहमत उनकी योग्यता पर लगाई गई हो। बीते कुछ वर्षों से लगातार यह प्रचारित किया जाता रहा है कि उच्च शिक्षा में रिक्तियों की पूर्ति न हो पाने की एक बड़ी वजह देश में शिक्षक बनने लायक पात्र युवाओं की अनुपलब्धता है। लेकिन यह तर्क इसलिए सटीक नहीं बैठता कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष 25 हजार युवा पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा यूजीसी, आईसीए और आईसीएस द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में औसत 50 हजार युवा जेआरएफ या नेट परीक्षा पास करते हैं।

राज्यों की सेट परीक्षा में 25-30 हजार युवा सफल होते हैं। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर साल करीब एक लाख दावेदार शिक्षक उपलब्ध होते हैं। बीते 10 सालों में करीब 10 लाख उपलब्ध आवेदकों की तुलना में कुल प्राध्यापकों की रिक्तियां सिर्फ पांच लाख हैं। यदि सभी रिक्त पद भर दिए जाएं तब भी पांच लाख योग्य आवेदक शेष रह जाएंगे। साफ है कि समस्या युवाओं में कौशल की कमी की नहीं उन्हें नियुक्त करने की इच्छा शक्ति की है।

यदि केंद्र और राज्य सरकार मिल कर एक यथेष्ठ कार्ययोजना के तहत देश के सभी उपलब्ध योग्य आवेदकों का पंजीयन करें तो यह बात खुद ही साफ हो जाएगी कि देश में काबिल युवाओं की कोई कमी नहीं है। इन युवाओं को दरकिनार कर बुजुर्ग सेवानिवृत्त प्राध्यापकों से काम चलाना न तो समस्या का स्थायी समाधान है और न ही इससे अपेक्षित परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। अगर हम वाकई भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा में बढ़ रहे नामांकन के अनुपात में शिक्षकों की रिक्तियों की पूर्ति की जाए और काबिल, ऊर्जावान युवाओं को देश का भविष्य संवारने के लिए इन पदों पर नियुक्त किया जाए।

● *देवेंद्र जोशी, महेश नगर, उज्जैन*

एनआरसी से परहेज

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करना राज्यों ही नहीं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजी ने कहा है कि वे अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। राजनीतिक फायदे के लिए ममता बनर्जी एनआरसी का विरोध कर अपने वोट बैंक यानी वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। तुष्टिकरण की नीति पर चलने वाली कांग्रेस के हश्र से तृणमूल कांग्रेस को कुछ तो सबक लेना चाहिए।

● *राम मूरत 'राही', सूर्यदेव नगर, इंदौर*

साझा मकसद

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान पेंशन योजना के प्रति कुछ प्रदेश सरकारों का रुख उदासीन बना हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो इन योजनाओं के तहत एक भी किसान का डाटा केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों का रवैया भी उत्साहवर्धक नहीं है। गौरतलब कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के चलते उसने देश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस समस्या का हल खोज लिया है। अब किसान अपनी अकेले की जानकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को भेज सकते हैं। मंत्रालय इसे दर्ज करके योजना का लाभ सभी किसानों को दे सकता है। किसान हितैषी और जन कल्याणकारी योजनाओं में राज्य सरकारों को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। आम जनता को राहत पहुंचाना सभी सरकारों का साझा उद्देश्य होना चाहिए।

● *ललित महालकरी, इंदौर*

हादसों के मद्देनजर

इसमें संदेह नहीं कि सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण वाहन चालकों की लापरवाही होती है, लेकिन सड़कों के डिजाइन में खामी, उनके गड्ढे, किनारों पर अतिक्रमण, आवारा पशु और रोशनी की कमी आदि के कारण भी हादसे होते हैं। स्पष्ट है कि सड़कों के बेहतर रखरखाव के साथ ही यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की जानी चाहिए। क्या यह उचित नहीं होगा कि सड़कों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वालों को भी भारी जुर्माने का भागीदार बनाया जाए? कम से कम यातायात पुलिस के संख्याबल के अभाव को तो प्राथमिकता के आधार पर दूर किया ही जाना चाहिए। चूंकि भारी जुर्माने के प्रावधान अमल में आने के बाद अवैध वसूली का भी अंदेशा है, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से लैस हो। यह भी आवश्यक है कि सरकारी वाहन किसी तरह की रियायत न पाने पाएं और भारी वाहनों पर खास निगाह रखी जाए। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के मकसद को पूरा करने में संकीर्ण राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, लेकिन यह एक विडंबना ही है कि कुछ राज्य सरकारें असहयोग का प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर*

किस पर विश्वास

राजस्थान में घटित हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के तहत बसपा के सभी छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की खबर से उन मतदाताओं को काफी निराशा हुई होगी जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाते हुए बसपा के प्रति अपना विश्वास जताया होगा। निस्संदेह इस प्रकार की हरकतें जनमत के साथ धोखा और लोकतांत्रिक मूल्यों को धता बताने वाली हैं। पूरी तरह स्पष्ट है कि सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं की न तो कोई विचारधारा होती है और न ही जनमत के प्रति कोई प्रतिबद्धता। ऐसे में भला जनता किस पर विश्वास जताए?

विडंबना है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी सामने आती रही है। देश के बड़े राजनीतिक दलों को राजनीतिक शुचिता बरकरार रखने के लिए ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। लोकतंत्र में जनमत के साथ धोखाधड़ी का यह चलन शीघ्र ही बंद होना चाहिए।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली